[श्री बृजप्रिय मौर्य]

देखा गया और दस्तखत हो गये। जिस समय हम मिले थे तो हमें दोनों ही नेताओं ने बताया कि आप लोगों ने मिलने में देरी की, यह अब हो चुका है। यह उनका दुर्भाग्य रहा। श्रीमन्, उसी समय से लगातार चाहे पूर्वी पाकिस्तान का जमाना रहा, चाहे स्वर्गीय मुजीबुरहमान का जमाना रहा हो, चाहे आज का जमाना हो, तब से इन बुद्धिस्ट निहत्थे लोगों पर लगातार आक्रमण होते हैं।

श्रीमन्, उस समय वहां पर एक करुनाकुल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना, उसमें भी करीब 1 लाख लोग, चकमाज लोग बेघरबार हो गये थे और 40 सैकड़ा इनकी जमीन खेती के योग्य जो थी, पानी में डूब गई थी। श्रीमन् मैं इस विषय को ज्यादा देर तक नहीं लेना चाहता, बहुत सी पेपर-कटिंग हैं कि वहां पर किस तरह से छोटे-छोटे बच्चों को फौज के द्वारा मारा जाता है, ये तमाम फोटो यहां पर निकले है, लगातार वहां से इस तरह की खबरें आती रहीं हैं।

मैं तो श्रीमन्, माननीय विदेश मंत्री जी के इस बयान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपके द्वारा इस सरकार का उन्होंने इस सदन में और उस सदन में भी आश्वासन दिया था कि जो चकमा के रेफ्यूजीज हैं उनको बंगला देश भेजा जायेगा ऐसे वातावरण में भेजा जायेगा जिसमें वे सुरक्षित रह सकें। मैं उसी को कोट करके अपनी बात समाप्त करूंगा।

"Mr. P. V. Narasimha Rao, External Affairs Minister, admitted in the Lok Sabha today that there was a large influx of Chakma and other tribals from Bangladesh into Tripura and other adjacent States recently.

He said the Government had stressed in that context that adequate assurances should be given to the refugees so that they could return with honour and dignity."

यही नहीं एक टीम भी वहां गई थी। उस टीम ने जा कर यह कहा था कि हम को सिर्फ बंगाल में रहने ही नहीं दिया हमें देखने भी नहीं दिया कि वातावरण कैसा है। हम इस विचार के हैं कि अभी इनका भेजना ठीक नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आंकड़े देना बेकार है। पांच हजार किलोमीटर जमीन एक तरह भारत का अटूट अंग थी। यह दुर्भाग्य से चली गई। न्यू मोर आइलैंड की बात बंगलादेश पैदा कर सकता है लेकिन इसका प्रश्न नही उठता। मैं स्वयं यह महसूस करता हूं कि यह भारत का अटूट अंग था और इसके लिये भारत सरकार की ओर से कोई कदम उठाया जाना चाहिये। जो निहत्थे, बौद्ध ट्राइबल हैं वहां के लोग इनको न मारें। बुद्धिस्टों की एक कांफ्रेंस हुई थी उनको विश्वास दिलाया गया था और प्रधान मंत्री जी से बुद्धिस्टों का एक दल मिला था; उनको यह आश्वासन दिया गया था कि उनके जान-माल की रक्षा की पूरी कोशिश की जायेगी। इसके लिये भारत सरकार पूरा प्रयत्न करेगी कि उनकी हत्या न की जाए। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हू और आपका फिर से आभार मानता हूं कि यह सब कहने के लिये आपने मुझे इजाजत दी।

REFERENCE TO THE WINDING UP OF THE CENTRAL FISHERIES CORPORATION LTD., HOWRAH.

SHRI ARABINDA GHOSH (West Bengal): Sir, I want to make a Special Mention about the winding up

of the Central Fisheries Corporation Ltd. Howrah (West Bengal), rendering 400 workers and employees jobless.

Consequent upon the winding up of the Central Fisheries Corporation Ltd. Howrah, the management has been taking speedy steps to close down the Corporation. Already they have completed the process of closing down the Madras unit. Thus, all employees, including 150 casual and 236 regular, are in the verge of retrenchment and their dependents facing starvation after rendering 10 to 12 years of qualified service. Practically, they have spent the best time of their youth in this concern and moreover they are all experienced people.

The Central Fisheries Corporation can be revived and made viable again by changing its organisational frame, system and policy of business with efficient management for operating its business with a view to achieving the objectives recommended by the Committee on Public Undertakings on 26th April, 1979 and initiated by the hon'ble Minister of Agriculture, Rao Birendra Singh for immediate implementation. Otherwise the process of final winding up may kindly be kept in abeyance till all the staff of the Corporation (236 regular and 150 casual) are absorbed specifically in the following undertakings of the Agriculture Ministry and the Government of India without applying any condition and elsewhere specially in West Bengal where a majority of the workers and employees are working:

1. The Food Corporation of India.

2. Central Warehousing Corporation.

3. National Seeds Corporation.

4. India Dairy Corporation.

5. Haldia Port and all other Public Undertakings of Government of India and West Bengal.

Myself, Shri Sourendra Bhattacharjee, M.P. of this House, along with Opposition Leader Shri Samar Mukherjee M.P. Lok Sabha, met the Minister of Agriculture, Rao Birendra Singh, yesterday and discussed about the fate of the Central Fisheries Corporation Ltd. and absorption of these employees and workers. The hon. Minister assured us that he would do his best so that the said experienced people are not thrown out of employment.

REFERENCE TO THE DIFFICULTIES FACED BY WEAVERS IN VARANASI AND AZAMGARH ON ACCOUNT OF INCREASE IN PRICES OF SILK YARN

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं वाराणसी और आजमगढ़ जिले के उन बुनकरों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिन्होंने पिछले महीने रेशम, सिल्क यार्न के एकाएक भाव में बढ़ोतरी हो जाने के कारण सारे अपने हथकरघों को बन्द कर दिया था, एक तरह से उनके सामने जीवनयापन की समस्या विकराल रूप धारण करके खड़ी हो गई थी। सिल्क यार्न का दाम एकाएक बढ़ाया गया इसके पीछे ऐसा लगता है कि जहां रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है विशेषकर कर्नाटक प्रदेश में वहां जो पहले रेशम खरीदने का सिस्टम था उसको समाप्त करके उन्होंने नीलामी सिस्टम लागू कर दिया। अब उसका परिणाम यह हुआ कि बड़े-बड़े पूंजीपति रेशम को खरीद करके उन्होंने अपने गोदामों में रख लिया, बाहर जाना रेशम बन्द हो गया। नतीजा यह हुआ कि रेशम का दाम अपने आप बढ़ गया और जुलाई महीने में जो रेशम 360 रुपये से लेकर 425 रुपये के बीच में प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलता था वह बढ़ कर के 850 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति